

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर



अपील संख्या 119/2014

पीठासीन अधिकारी



करतार सिंह पूनियाँ  
RAS

1 सुखवीर पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी लक्ष्मण का बास पोस्ट कटराथल तहसील व जिला सीकर।

अपीलांत

सत्यमेव जयते

1 सवाईसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह जाति राजपुत निवासी सिद्धासन तहसील व जिला सीकर।

Web Copy - Not Official

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 21.07.2014  
पारित द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
सीकर उनवानी सवाईसिंह बनाम सुखवीर  
आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 108/2011

Law  
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर



1. श्री महावीर प्रसाद खीचड़ अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री निर्मल कुमार शर्मा अधिवक्ता रेस्पोंडेंट

—निर्णय—

दिनांक:—28.09.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा आयोजन संख्या 108/2011 में पारित निर्णय दिनांक 13.07.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोंडेंट ने आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 186,187 वाके ग्राम सिंहासन तहसील व जिला सीकर के सन्दर्भ में प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा चाही विचारण न्यायालय ने अप्रार्थी का जवाब प्राप्त कर उभयपक्ष की साक्ष्य लेकर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट सदभावी केता है अपीलांट ने 20.06.2011 को पंजीकृत विक्रय पत्र से भूमि खरीद कर खातेदार काश्तकार काबिज है रेस्पोंडेंट

*lavo*  
 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
 पदेन राज्य अपील अधिकारी  
 सीकर



भंवरसिंह का उत्तराधिकारी नहीं है, वारिस नहीं है भंवर सिंह के वारिस अन्य है विवादित लिखावट में खसरा नम्बर अंकित नहीं है लगान की रसीद पेश नहीं की गई है। केवल मात्र दो तीन साल की गिरदावरी पेश की है सजरा खानदान के अनुसार गोदनामे के विरुद्ध वाद सिविल न्यायालय में खारिज हो चुका है अपीलांत खातेदार काशतकार है जिसे पाबंध किया गया है जो विधि विरुद्ध है अपील स्वीकार की जायें अपीलांत ने अपने कथनों के समर्थन में आर.एल.डब्ल्यू 2008 पेज 1036, आर.एल. डब्ल्यू 2009 (1) पेज 376 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये हैं।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि जागीर पुन ग्रहण के उपरान्त भैरुराम के नाम दर्ज हुई भैरुराम ने लिखावट की खसरा गिरदावरी से भंवर सिंह का कब्जा काशत साबित है भैरूसिंह के जीवनकाल में दावा कर दिया था। भैरूसिंह ने वाद कथन को अस्वीकार नहीं किया भैरूसिंह दो वर्ष पहले मरा है लिखावट के समय के सभी गवाह मर चुके हैं उनके वारिसों ने हस्ताक्षरो को प्रामाणित किया है। विक्रय पत्र निरस्त करवाने का दावा लम्बित है। लिखावट 30 वर्ष पुरानी है जिसके सत्य होने की अवधारणा की जाती है विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपने कथनों के समर्थन में आर.एल.डब्ल्यू 2009(1) आर.जे. पेज 339 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस एवं उनके द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन एवं मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोंडेंट विवादित भूमि के सन्दर्भ में प्रार्थी के पिता की लिखावट दिनांक 16.07.1954 एवं खसरा गिरदावरी संवत् 2011, 2012 व 2013 के आधार पर आवेदन लेकर आया है। जबकि अपीलांत दिनांक 20.06.2011 के रजिस्टर्डड विक्रय पत्र,

Lesio  
 जु-प्रखण्ड अधिकारी एवं  
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
 सोकर



नातान्तकरण संख्या 769 दिनांक 05.07.2011 के आधार पर आवेदन खारिज करने का कथन करके आये है।

विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से विवादित भूमि के सन्दर्भ में अपीलांट को ताफैसला वाद प्रार्थी के कब्जे काशत में दखल नही करने व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद किया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिकारों का निर्णय मूल वाद में होना है उभयपक्ष के मध्य वाद विवाद नही बढ़े इसे दृष्टिगत रखते हुये विचारण न्यायालय द्वारा पारित मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश विधि सम्मत प्रतीत होता है किन्तु अधिकारों की घोषणा के बिना किसी एक पक्ष का कब्जा मानते हुये अपीलांट को इसमें दखल नही करने के लिए पाबंद किया जाना विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाता है एवं उभयपक्ष को वाद के निस्तारण तक विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंध किया जाता है। इसी अनुरूप अपील का निस्तारण किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

28/9/18  
 (करतार सिंह पूनियाँ)  
 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
 पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,  
 सीकर